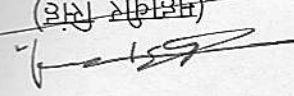


बाप जीधरपुर
 सहायक कलेक्टर
 (महलीर सिंडी)


निर्णय से इजलास आज दिनांक 13/3/2020 को सुनाया गया।

इकेर नम्बर से कम हो।

स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल वगैरह प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपडित धारा 151 सी.पी.सी का

आदेश

है।
 तथा वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी के मध्यनजर रखते हुए खारिज किया जाता
 नहीं किया जा सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है
 तथा दस्तावेजी दस्तावेज के अभाव में विनाय वाद पैदा ही नहीं हुआ हो ऐसे वाद को स्वीकार
 नोटिस के अभाव में तथा वाद के सलन प्रस्तुत 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छूट का यथापिप्त
 सके। उक्त प्रकरण में वाद हेतुक ही प्रकट नहीं हुआ तथा वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के
 ही वाद को खारिज किया जाना उचित है। तार्कि न्यायालय का महत्वपूर्ण समय भी बचाया जा
 कियाओं के परिचालन से होने वाले समय के लिये कुछ प्रवृत्ति के वादों को प्रारम्भिक स्तर पर
 जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा धारा 151 सी.पी.सी के तहत इस प्रकार के प्रयोग, खर्चों तथा अनेक
 प्रतिपदित किया गया है कि सिर्फ एडवर्स पत्रदान के आधार पर खारिजी अधिकार नहीं दिया
 माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा भी समय समय पर किये गये निर्णयों के अनुसार यह सिद्धान्त
 की घोषणा कर वादीगण को खारिजी अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में
 न्यायालय के विनम्र मत में सरकारी मूंसि पर एडवर्स पत्रदान के आधार पर खारिजी अधिकारों
 किसी प्रकार का अनुलोष प्रसि हेतु कोई सारवान लक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस
 गलत है। अप्रार्थी का वाद जारिये उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज करमाया जावे। प्रस्तुत वाद में
 अतिकसी है तथा वादीगण अतिकमण के आधार पर सरकारी मूंसि को हड़पना चाहता है जो कि
 प्रस्तुत किया है। प्रार्थी तहसीलदार बाप से अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि अप्रार्थी (वादीगण)
 राजकीय सिवाय चक मूंसि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसके आधार पर घोषणात्मक वाद
 का अध्ययन किया गया। बाद मनन अवलोकन व विनान के पाया गया कि वादीगण द्वारा
 दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपडित धारा 151 सी.पी.सी
 उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध

